अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों की सूची में संशोधन करने के संबंध में सलाहकार समिति की सिफारिशें

*197. **श्री महेश्वर सिंह :** क्या कल्याण मंत्री 22 अप्रैल, 1994 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न 365 के दिए गए उत्तर को देखें और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन करने के लिए सचिव (कल्याण) की अध्यक्षता में गठित की गई सलाहकार समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो कब और उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

दुग्ध उत्पादन में वृद्धि

*198. **श्री राम जेठमलानी :**
श्री कृष्णलाल शर्मा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्षों में देश में दुग्ध उत्पादन में भारी वृद्धी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1993-94 के दौरान देश में दुग्ध-उत्पादन कितना था ;

(ग) क्या यह सच है कि भारत ने दुग्ध उत्पादन के मामले में विश्व में दूसरा स्थान प्राप्त लिया है ;

(घ) क्या यह सच है कि दुग्ध उत्पादन के साथ-साथ दुग्ध के सामन्य उपभोक्ता मूल्य में भी वृद्धि हुई है ;

(ङ) यदि हां, तो देश में आज राष्ट्रीय स्तर पर दुग्ध का औसत उपभोक्ता मूल्य कितना है ;

(च) क्या यह सच है कि दुग्ध का उपर्युक्त मूल्य अधिकांश लोगों, विशेषकर गरीबी-रेखा से नीचे जीवनयापन कर रही देश की 40 प्रतिशत आबादी की पहुंच से बाहर है ; और

(छ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) और (ख) वर्ष 1990-91 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान दूध का उत्पादन क्रमशः 53.9, 55.7 तथा 57.8 मिलियन टन हुआ ।

(ग) जी, हां ।

(घ) और (ङ) दूध का उपभोक्ता मूल्य उत्पादन लागत, संग्रहण प्रशीतन, प्रसंस्करण आदि जैसे घटकों पर निर्भर करता है । दूध का मूल्य , प्रचूरता वाले मौसम (नवम्बर—फरवरी) में न्यूनतम तथा कमी वाले मौसम (मई से अगस्त तक अधिकतम रहता है । देश में वर्ष 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान सहकारी समितियों/सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा बेचे गए दूध का औसत मूल्य क्रमशः 6.4, 7.5 तथा 8.0 रुपये प्रति लिटर था ।

(च) दूध की खपत आमदनी के हिसाब से घटती-बढती रहती है तथा निम्न स्तर के लोगों में यह पौषणिक आवश्यकता से नीचे होती है ।

(छ) गरीबी रेखा से नीचे की जन-संख्या के पौषणिक स्तर को बढाने के लिए विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं।

Assistance sought by Madhya Pradesh for flood affected farmers

*199. SHRI AJIT P. K. JOGI:
SHRI RAM GOPAL YADAV:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the assistence sought by Government of Madhya Pradesh for providing relief to the farmers affected by recent floods has been released;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether any memorandum has been received regarding inadequate amount of assistance and amendment in the norms of relief or compensation;

(d) if so, the details thereof; and

(e) the action taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI BALRAM JAKHAR): (a) and (b): In addition to the normal release of the first and second instalments of the Central share of Calamity Relief Fund (CRF) for the year 1994-95, Government of India have also released the third instalment amounting to Rs. 6.9375 crores in advance, in order to enable the Government of Madhya Pradesh undertake relief measures incluing assistance to affected farmers. The fourth instalment is also baing released shortly.

(c) to (e): Government of Madhya Pradesh has represented to the X Finance Commission for enchancing the Annual allocation to the State CRF from the present level of Rs. 37.00 crores to Rs. 160.00 crores. The Commission is reviewing the existing Scheme for Financing Relief Expenditure in the wake of natural calamities as also the allocation under the CRF.

Demand to liberalise mining Policy

*200 SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of MINES be pleased to state:

(a) whether the Federation of Indian Mineral Industries has demanded further liberalization in Government's mining policy;

(b) if so, the details of the demands made by the Federation of Indian Mineral Industries;

(c) whether Government propose to examine the views of the Federation of Indian Mineral Industries and also to liberalise the mining palicy; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINES (SHRI BALRAM SINGH YADAV): (a) to (d) No, Sir. However the Federation of Indian Mineral Industries has suggested inter-alia amendmentsS to the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957, doing away with premature termination of leases, prescribing minimum area for mining lease, deletion of First Schedule of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957, doing away with mining plan for less important minerals, etc.. After considering suggestions received from State Governments and other organisationns including the Federation of Indian Mineral Industries, the Act was recently amended by enactment of the Mines and Minerals (Regulation and Develpment) Amendment Act, 1994. No further amendments are proposed for the time being.

Shortage of Eggs

1540. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is an overall shortage of eggs in the market, if so, whether Government propose to import eggs;